Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन

डॉ. अरुण कुमार सिंह*

* सहायक प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) मुल्तानीमल मोदी कॉलेज (चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध), गाजियाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में एक लम्बे अर्शे से हाशिए का स्थान दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों की उपेक्षा के नतीजन हमारी शिक्षा व्यवस्था 21वीं शताब्दी के बदलते ज्ञान के वैश्विक स्वरुप में अपनी प्रासंगिकता खोती नजर आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्तमान की विषंगतियों को संज्ञान लेते हुए व्यावसायिक और कौशल विकास के विषयों को अपने नवीन दस्तावेज में मुख्य स्थान दिया है। प्रस्तावित आलेख के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं की विवेचना की गयी है साथ ही इससे जुड़े चुनौतियों पर ध्यानाकृष्ट किया गया है।

शब्द कुंजी – व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तकनीकी।

प्रस्तावना – आज हम एक तकनीकी क्रांति के कगार पर खड़े हैं या अधिक लोकप्रिय रूप में इसे चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है जो मौलिक रूप से हमारे जीवन स्तर को, कार्य संस्कृति को और एक दूसरे के साथ सम्प्रेषण के तरीके को आमूल चूल तरीके से परिवर्तित कर रहा है। इस तकनीकी नवाचार ने हमारे रोजगार के पारंपरिक तरीकों को बदलना शुरू कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप नौकरी के पारम्परिक उपलब्ध अवसरों की संख्या सीमित हो गई है और वैश्विक फलक पर ऐसे क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं जहाँ पर लोगों के कौशल और पुन: कौशल की आवश्यकता बढ़ गई है। हाल ही के कोरोना नामक गंभीर महामारी ने इस बात को और पुख्ता तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान परिदृश्य में दुनिया में वृद्योन्मुख जनसंख्या एक समस्या के रूप में उभरी है ऐसे में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के पास अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो सबसे युवा वर्ग की आबादी की बहुतायत है। भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या की आबादी का लगभग 62.5% हिस्सा है जो की 15 से 59 वर्ष की आयु के हैं। भारत दुनिया के युवा जनसांख्यिकी का पांचवां हिस्सा है और यह जनसंख्या लाभ 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाल ही के जनसंख्या प्रक्षेपण से पता चलता है कि 2041 तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के अगले दौर में प्रवेश कर गया है जिसमें अगले दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी हालांकि, यदि तेजी से बढ़ती हुई भारत की युवा आबादी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा से वंचित रहकर गर अकुशल रह जाती है या उनकी क्षमताओं का समय रहते कुशलतापूर्वक उपयोग न किया गया तो यह अनुमानित जनसांख्यिकीय लाभांश आसानी से जनसांख्यिकीय आपदा में भी बदल सकता है जो हमारे सामाजिक-आर्थिक विकास की संभावनाओं को कम कर सकता है। (जीबीसी-शिक्षा), शिक्षा आयोग, और यूनिसेफ के सहयोग से लर्निंग आउटकम पर आधारित 2019 कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 का अनुमान है कि भारत में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों में लगभग 47% युवकों के पास रोजगार के लिए आवश्यक शिक्षा और पर्याप्त कौशल का अभाव होगा। एक अन्य अध्ययन का अनुमान है कि हर साल स्नातक होने वाले पचास लाख छात्रों में से केवल 20 प्रतिशत भारत में रोजगार प्राप्त करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच इस तरह के अधिक निष्कर्ष और पूर्वानुमान भारतीय युवाओं की रोजगार योग्यता की निराशाजनक स्थिति को दर्शा रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा कमीशन की गई एक अलग नई रिपोर्ट ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में रोजगार रहित शिक्षा के अंतर्निहित कारणों में प्राथमिक कारण यह बताया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति की निम्न गुणवत्ता में व्यावसायिक प्रशिक्षण का समावेश न होने से अक्सर छात्रों द्वारा अर्जित शिक्षा और नियोक्ता या बाजार (कृषि , उद्योग , व्यापार आदि) द्वारा आवश्यक कौशल के बीच मांग-आपूर्ति का वृहद अंतर होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शिक्षा नीति निर्माताओं के लिए मुख्य चिंता न केवल युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों के के मुद्दे को संबोधित करना है, बल्कि कार्यस्थल पर वर्तमान और भविष्य के जरूरतों के अनुसार उनकी रोजगार क्षमता में अभिवृद्धि करना है। शिक्षा और कौशल विकाश में व्याप्त भारी असंतुलन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) का गठन किया है और इसके दायरे में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), कौशल भारत, संकल्प की शुरुवात की है। इसी क्रम में शिक्षा व्यवस्था में कौशल विकास को अन्तर्निहित करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रस्तावित किया गया है इस नवीन शिक्षा नीति में कौशल विकास की समस्या के निदान के लिए शुरुवाती प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक और कौशल नवाचार से सम्बंधित पाठ्यक्रमों की पुरजोर वकालत की गई है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का

संकल्प पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक क्रांतिकारी दस्तावेज बनाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और व्यावसायिक शिक्षा –नई शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि पर जोर देने के साथ-साथ युवाओं के समग्र विकास की परिकल्पना भी की गई है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन, 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्यों को साकार करने के लिए युवाओं में कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एक निर्धारण कारक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनईपी 2020 के प्रस्तावित नीति दस्तावेज में कुल 66 पृष्ठों में व्यावसायिक शब्द की 76 बार पुनरावृत्ति हुई है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनईपी 2020 के 66 पृष्ठीय नीति दस्तावेज में व्यावसायिक शब्द की 76 बार पुनरावृत्ति हुई है। पूरे नीतिगत दस्तावेज में शिक्षा को अर्थव्यवस्था के विकास, रोजकर के सृजन और उद्यमिता के विकास से परस्पर जोड़ कर देखा गया है। यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन निम्न पहलुओं में सूचीबद्ध किया गया है।

अनुशासनात्मक पदानुक्रम को निर्मूल करना –मौजूदा अकादमिक व्यवस्था में अनुशासनात्मक पदानुक्रम देखा जा सकता है जहाँ तकनीकी और विज्ञान के विषयों को अन्य कला या समाज विज्ञान के विषयों के बनिस्पत श्रेयस्कर समझा जाता है NEP 2020 ने नवीन प्रयास किया है कि कला और विज्ञान के विषयों के बीच , पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच कोई दुराव न हो य विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान किया गया है , जिससे शिक्षार्थियों के पास अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुरूप विषयों और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से जीवन में वे अपना जीविका पथ खुद चुन सकेंगे य ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के विषयों में बहुविषयकता और समग्र शिक्षा पर बल दिया गया है (NEP 2020, P.5)

व्यावसायिक शिक्षा का संवेदीकरण – व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से हीन माना जाता है इस वजह से बहुसंख्यक छात्र जो किसी कारणवश मुख्यधारा की शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते उनके रोजगार के विकल्प इस धारणा से प्रभावित होते हैं। इस गंभीर समस्या को स्वीकारते हुए नई शिक्षा नीति ने अथक प्रयास किया है कि भविष्य में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति के पदानुक्रम को समाप्त करना है और चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षण संस्थानों (प्राथमिक से उच्चा शिक्षा) में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करना है। शिक्षा मंत्रालय , व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ और उद्योग क्षेत्र के सहयोग से सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय समिति के जरिए उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षुता के विभिन्न मॉडलों का अभिनव प्रयोग किया जाएगा और साथ में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थानों में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। महात्मा गांधी के नई तालीम को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्ययन के दौरान कम से कम एक व्यवसाय सीखे और कई अन्य व्यवसाय से परिचित हो इससे लोगों में श्रम की गरिमा का भाव उत्पन्न होगा साथ ही भारतीय कला और कारीगरी से जुड़े विभिन्न व्यवसायों की बदलते समय में दोबारा प्रासंगिकता मिलेगी (NEP 2020, P.5)

शिल्प आधारित शिक्षा कौशल अभिमूल्यन के लिए विद्यालयी प्रशिक्षण व्यावसायिक नवाचार को बुनियादी तौर पर संवर्धन करने के उद्देश्य से छठवीं से लेकर आठवीं कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक मनोरंजक पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्पों के नमूने का सर्वेक्षण और व्यावहारिक अनुभव दिया जाएगा प्यावसायिक विषयों को सीखने के लिए स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की कौशल विकास आधारित गतिविधियों जैसे कला, प्रश्नोत्तरी, खेल और व्यावसायिक शिल्प को समृद्ध करने के लिए पूरे वर्ष बैगलेस दिनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ बच्चों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के स्थानों/स्मारकों का दौरा, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और उनके गांव/तहसील/जिला/राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा करने के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए समय-समय पर अनावृत्ता किया जाएगा (NEP 2020, P.16)

21वीं सदी के क्षमता निर्माण के लिए व्यावसायिक शिक्षा – हमारा वैश्विक समाज ज्ञान के परिदृश्य में तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ, जैसे कि बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय, दुनिया भर में कई अकुशल रोजगार को मशीनों द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। ऐसे बदलाव के दौर में हमें एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी जो न केवल तकनीकी और विज्ञान के विषयों में निपुण हो वरन सामाजिक विज्ञान, मानविकी और कला जैसे विषयों की व्यावहारिक समझ भी रखते हों। विभिन्न वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधन, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और पानी की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए, महामारी से उत्पन्न संक्रामक रोग के प्रबंधन और टीकों के विकास में विज्ञान और मानविकी के विषयों में सहयोगात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होगी प एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी क्षमताओं जैसे बौद्धिक, सौंदर्य विषयक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिकता को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा।

अंत:क्रियाशील, अंत:अनुशासनात्मक और परिणाम आधारित शिक्षा NEP 2020 में एक उच्चतर शैक्षणिक परिषद् (HECI) का गठन प्रस्तावित है जो कि सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी) का कार्य करेगी। सामान्य शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को तैयार करेगी, जिसे 'स्नातक विशेषता' कहा जाएगा। जीईसी द्वारा एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ) भी तैयार किया जाएगा और यह उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के साथ तालमेल बिठाएगा। डिग्री/ डिप्लोमा प्रमाणपत्र के लिए उच्च शैक्षिणिक योग्यता का निर्धारण एनएचईक्यूएफ द्वारा सीखने के परिणामों के संदर्भ

में किया जाएगा। इसके अलावा, जीईसी, एनएचईक्यूएफ के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर, तुल्यता आदि जैसे मुद्दों के लिए सुविधाजनक मापदंड स्थापित करेगा। जीईसी को विशिष्ट कौशल की पहचान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा जिसे विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के दौरान हासिल करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा का उद्देश्य ऐसे कुशल शिक्षार्थियों को तैयार करना है जिनके पास 21वीं सदी के कौशल की पर्याप्त जानकारी हो।

श्रम बाजार उन्मुखीकरण, एकाधिक – प्रविष्टि, निकास – उच्च शिक्षा में डिग्री कार्यक्रमों की संरचना और अवधि में लोचशीलता प्रदान की गयी है। स्नातक डिग्री तीन से चार वर्षों की अवधि की होगी इस अवधि के अंदर विभिन्न प्रविष्टि , निकास विकल्पों का प्रावधान किया गया है उदाहरण के लिए, व्यावसायिक क्षेत्रों सहित किसी विषय या क्षेत्र में एक वर्ष पूर्ण करने के बाद विधार्थी अगर किसी कारणवश अपनी पढाई आगे जारी नहीं रख सकता तो वह प्रमाण पत्र अर्जित कर सकता है गर दो वर्ष पूर्ण करता है तो डिप्लोमा या तीन वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। हालांकि, चार वर्षीय बहु–विषयक स्नातक कार्यक्रम शिक्षार्थियों का पसंदीदा विकल्प होगा क्योंकि यह छात्र की स्वयं के पसंद के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर विषयों पर ध्यान देने के साथ– साथ समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने के अवसर से लाभान्वित होगा। एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना की जाएगी जो विभिन्न मान्यता प्राप्त एचईआई से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा ताकि एचईआई से डिग्री अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जा सके।यदि कोई छात्र भ्म्प् द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र (क्षेत्रों) में एक गहन शोध परियोजना को पूर्ण करता है तो वह चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम 'अनुसंधान के साथ' डिग्री भी प्राप्त कर सकता है।

व्यावसायिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास – शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी) के तहत एक पेशेवर मानक निर्धारण निकाय (पीएसएसबी) के रूप में अपने पुनर्गठित नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा। इस मानक में विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका की अपेक्षाओं और उस चरण के लिए आवश्यक दक्षताओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक चरण के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन के मानक भी शामिल होंगे जो एक निश्चित आवधिक आधार पर किए जाएंगे। एनपीएसटी पूर्व शिक्षक शिक्षा सेवा कार्यक्रमों के प्रारूप के बारे में भी सूचित करेगा। तत्पश्चात राज्यों द्वारा इसे अपनाया जा सकता है और शिक्षक कैरियर प्रबंधन के सभी पहलुओं को निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें कार्यकाल, पेशेवर विकास प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य मान्यताएं शामिल हैं। पदोन्नति, वेतन वृद्धि, कार्यकाल की अवधि अब वरिष्ठता के आधार पर नहीं होगी, बल्कि केवल ऐसे मूल्यांकन के आधार पर होगी। 2030 में पेशेवर मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा, और उसके बाद हर दस साल में, सिस्टम की प्रभावकारिता के गहन अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा।

भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली की चुनौतियाँ – हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 ने एक कुशल कार्यबल बनाने में सैद्धांतिक तौर पर उल्लेखनीय प्रयास किया है फिर भी कई गंभीर चुनौतियाँ हैं जिन्हें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूर करना होगा।

1. **बुनियादी सुविधाओं का अभाव–** हाल ही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2020 को सत्र 2021–22 में क्रियान्वित किया गया है। कौशल विकास से जुड़े विषयों के अध्यापन में निम्नांकित कमियां महसूस की गयी है य एक वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक को मशरुम की खेती जैसे कौशल पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए सबसे प्राथमिक तौर पर एक बोटैनिकल गार्डन चाहिए उसी तरह जंतु विज्ञान में मतस्यकी को व्यावहारिक तौर पर सीखाने के लिए तालाब चाहिए जिसका बहुतायत महाविद्यालयों में अभाव देखा गया है। अवसंरचना के अभाव में कौशल के पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक स्तर पर सीमित रह जाएंगे।
2. **अनुभवी और योग्य शिक्षकों की कमी –** व्यावसायिक शिक्षा सुधार के लिए योग्य प्रशिक्षकों को प्रदान करना हमेशा एक बाधा साबित हुआ है। फैकल्टी की कमी और योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने और व्यवस्था में बनाए रखने के लिए शैक्षिक प्रणाली की अक्षमता कई वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही है। वर्तमान प्रणाली में शिक्षकों की संख्या और छात्र नामांकन में वृद्धि के साथ कोई आनुपातिक संतुलन नहीं है। उच्च शिक्षा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस पहलू पर ठोस ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. **कमजोर निजी और उद्योग भागीदारी –** उद्योगों के समर्थन के बिना, व्यावहारिक प्रशिक्षण बहुत समस्याग्रस्त हो गया हैय इसके अलावा, स्कूलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण की स्थिति व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में संतोषजनक नहीं है। वर्तमान में, ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि उद्यम पूर्व–नौकरी व्यावसायिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य हैं।
4. **प्रशिक्षण की गुणवत्ता उद्योग की मांगों के अनुरूप नहीं है –** शैक्षणिक संस्थाओ द्वारा प्रद्दत व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योगों की कौशल मांग में असम्बद्धता देखी जाती है जिसकी वजह से विद्यार्थी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं।
5. **पुराने प्रशिक्षण मॉड्यूल और अपर्याप्त पाठ्यक्रम –** व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकांश प्रशिक्षण संस्थान संरचनात्मक रूप से अनम्य होते हैं जहाँ पर पुराने केंद्रीकृत पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होती रहती है जिस वजह से ऐसे संस्थानों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी वर्तमान के बाजार अनुरूपी मांग को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

निष्कर्ष – निम्न कौशल गरीबी और असमानता का पोषण करते हैं। जब शिक्षा कौशल उन्मुख हो तो कौशल विकास के जरिए बेरोजगारी और अल्परोजगार को कम किया जा सकता है, श्रमिक उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और साथ ही जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। यूँ तो स्कूली शिक्षा रोजगार सुनिश्चित नहीं करती लेकिन कौशल विकास अगर व्यक्ति का हुआ है तो वह अवश्य ही स्वावलम्बी बन सकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को अपना ध्यान रटंत विद्या से हटाकर NEP 2020 में अन्तर्निहित रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच पर केंद्रित करना होगा। एक आउट–ऑफ–द–बॉक्स सोच और नवाचारों के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थी में निर्णय लेने के आत्म विश्वास का बोध होगा। वर्तमान आधारभूत संरचना और संसाधनों की कमियों को दूर करते हुए अगर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को एक

ईमानदार राजनैतिक इक्षाशक्ति के जरिए क्रियान्वयन किया गया तो निश्चित ही जमीन पर एक आदर्श बदलाव होगा। वह दिन दूर नहीं जब भारतीय युवा शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में उन्हें प्रदान किए गए व्यावसायिक, रोजगार योग्य और उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि संभावित नौकरी देने वाले होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Agrawal, T. (2012). Vocational educationAnd training in India: Challenges, statusAnd labor market outcomes. Journal of Vocational Education &Training
2. Das, Jenefer & Malik, Navita. (2022). Vocational Education & Entrepreneurship in NEP 2020. I. 30-32
3. Government of India, Minsitry of Finance, Economic Survey 2018-19
4. Government of India, Ministry of Human resource development- The National Education Policy (NEP) 2020 document
5. Jaiswal, R. Vocational Education & Skill Development in India. Tactful Management Research Journal.
6. Pathak, R. (2020). NEP 2020:A Road Map to Vocational Development. Journal ofArts, HumanitiesAnd Social Sciences.
7. http://www.indiavocationaleducationreview.com
8. https://www.nationalskillsnetwork.in/highlights-of-the-national-education-policy-2020/
9. https://www.udhyam.org/post/nep-2019-alignment-with-udhyam-shiksha
10. https://www.unicef.org/press-releases/more-half-south-asian-youth-are-not-track-have-education-and-skills-necessary

****